टाइम्स ऑफ़ पीडिया

ٹائمس آف پیڈیا

TIMES OF PEDIA

अनोखे अंदाज़ और निराले तेवर के साथ इंसाफ़ की डगर पर

NEW DELHI Page 12 Price Rs. 3.00

www.timesofpedia.com

WEEKLY HINDI, ENGLISH, URDU

WED 11 MARCH - TUE 17 MARCH 2026

VOL. 14. ISSUE 11

RNI No. DELMUL/2012/47011

उत्तम नगर मामला: बिना नोटिस नहीं चलेगा बुलडोज़र, उच्च न्यायालय में एमसीडी का भरोसा

नई दिल्ली। राजधानी के उत्तम नगर क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई को लेकर चल रहे विवाद के बीच नगर निगम ने उच्च न्यायालय में स्पष्ट किया है कि बिना उचित नोटिस दिए किसी भी निर्माण को नहीं गिराया जाएगा। यह आश्वासन न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ के समक्ष दिया गया, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई बंद कर दी।

यह मामला होली के दौरान हुई एक हिंसक घटना से जुड़ा है, जिसमें एक युवक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद आरोपी पक्ष की महिलाओं ने अदालत का रुख करते हुए आशंका जताई थी कि प्रशासन उनके घरों को अवैध घोषित कर बुलडोजर से ध्वस्त कर सकता है। जरीना और शहनाज नामक महिलाओं द्वारा दायर याचिकाओं में कहा गया था कि उनके परिवार के सदस्यों से पुलिस पूछताछ कर रही है और उन्हें डर है कि प्रशासन उनके घरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकता है।

लोकसभा में 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन रद, सदन में सामान्य हुई कार्यवाही

नई दिल्ली। संसद में पिछले कई दिनों से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। मंगलवार को लोकसभा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए फरवरी की शुरुआत में निलंबित किए गए आठ विपक्षी सांसदों का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया। इनमें सात सांसद कांग्रेस के और एक वामपंथी दल से संबंधित हैं।

यह निर्णय सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सदन में ध्वनिमत से पारित किया गया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता, पोस्टर प्रदर्शन या कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री का उपयोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की मर्यादा और 'लक्ष्मण रेखा' का पालन करने का आग्रह किया।

ज्ञात हो कि यह विवाद फरवरी 2026 में बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ था, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' का हवाला देते हुए डोकलाम और लद्दाख में चीन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास किया था। इस दौरान अध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर विपक्षी सदस्य नाराज हो गए और सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के दौरान कुछ सांसदों ने नारेबाजी की और अध्यक्ष की ओर कागज के टुकड़े उछाले, जिसके बाद आठ सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था। अब निलंबन वापस लिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई है और विधायी कार्य भी सामान्य रूप से संचालित हो रहे हैं।

इसी बीच, 12 फरवरी की घटना को लेकर सेना के कुछ सेवानिवृत्त अधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ एक खुला पत्र जारी किया है। पत्र में संसद में हुई घटना को लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताते हुए इसकी निंदा की गई है। पूर्व सैन्य अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं सदन की गरिमा के विपरीत हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों को आघात पहुंचाती हैं।

केजरीवाल का बड़ा दावा, प्रधानमंत्री को चुनावी चुनौती

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। गोवा में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि यदि आज दिल्ली में चुनाव कराए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को दस सीटें भी नहीं मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी साठ से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी।

केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव हारी नहीं थी, बल्कि चुनाव हथिया लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके कई नेताओं को कारागार में डालकर सरकार के कार्यों को प्रभावित किया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। मदिरा घोटाले में आरोपमुक्त होने का उल्लेख करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अब न्यायालय का निर्णय आ चुका है और देश की जनता भी समझ चुकी है कि वह ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके पांच प्रमुख नेताओं को कारागार में डालकर दिल्ली को ठप करने का प्रयास किया।

अपने संबोधन में केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें और उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से समाप्त करने का प्रयास किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रकार के कदमों से युवाओं को यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि राजनीति में आने पर उन्हें भी इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

केजरीवाल ने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी ने देश में 'कार्य की राजनीति' की शुरुआत की है, जबकि अन्य दल इस दिशा में पीछे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और जल जैसी मूलभूत सुविधाओं पर कार्य किया, जिससे जनता को सीधा लाभ मिला।

भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि राजधानी में स्वच्छता, जल आपूर्ति और सड़कों जैसी आधारभूत सेवाओं की स्थिति संतोषजनक नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं देने के बजाय केवल राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है।

अपने वक्तव्य के अंत में केजरीवाल ने दोहराया कि वह पीछे हटने वाले नहीं हैं और जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा कि यदि चुनौती देनी है तो कार्य के स्तर पर प्रतिस्पर्धा की जाए, न कि राजनीतिक दबाव के माध्यम से।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि केजरीवाल के इस वक्तव्य से आगामी चुनावों को लेकर सियासी वातावरण और अधिक गर्म हो सकता है। दिल्ली की राजनीति में इस प्रकार के तीखे बयान आने वाले समय में चुनावी रणनीतियों को भी प्रभावित कर सकते हैं।

रूप नगर पुल हादसे की होगी जांच, दिल्ली के सभी लोहे के पुलों का होगा संरचनात्मक परीक्षण

नई दिल्ली। राजधानी के रूप नगर क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में लगभग फ्फ वर्ष पुराना फुट ओवरब्रिज अचानक ढह गया। यह पुल पहले से ही जर्जर स्थिति में था और वर्ष ख्ख्‍ में इसे असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था, इसके बावजूद लोग इसका उपयोग कर रहे थे। हादसे में एक महिला के नाले में गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जिससे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है।

घटना के समय महिला पुल पर मौजूद थी। पुल गिरने के साथ ही वह नीचे नाले में जा गिरी। सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव दल मौके पर पहुंचा और महिला को बाहर निकाला गया, किंतु उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली अग्निशमन सेवा, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के दलों ने संयुक्त रूप से राहत एवं बचाव कार्य चलाया।

Editor/Owner/Printer/Publisher: Ali Aadil Khan, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar, Okhla, ND - 25. **Printed at:** Shobi Offset Press, 2818, Gali Gadhiaiya, Kuchachalan, Daryaganj, ND. -2

अमेरिका-ईरान तनाव में कहाँ हैं रूस और चीन?

Ali Aadil Khan
Editor

अमेरिका और इज़राइल के साथ ईरान के बीच चल रहे टकराव के बीच ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस को हमलों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है—अगर संघर्ष और बढ़ता है तो ईरान के साथ खड़े होने के दावे करने वाले देश रूस और चीन कहां तक उसका साथ देंगे ?

दुनिया की नज़र अब इसी पर टिकी है कि Russia और China दोनों के ही Iran के साथ मजबूत कूटनीतिक, व्यापारिक और सैन्य रिश्ते होने के बावजूद मौजूदा हालात में सिर्फ बयानबाज़ी तक सीमित रहेंगे या ये दोनों ईरान को समर्थन भी देंगे ?

ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका-इज़राइल के संयुक्त हमलों पर रूस की प्रतिक्रिया अब तक काफी सीमित दिखाई दी है। मॉस्को ने तेहरान के प्रति एकजुटता जरूर जताई, लेकिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे वह इस टकराव में सीधे शामिल होता नजर आए। Dmitry Peskov, जो Kremlin के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बावजूद हालात 'इतने खराब हो गए कि सीधे आक्रामकता तक पहुंच गए '। पेस्कोव (Peskov), रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के क्रेमलिन प्रेस सचिव और उप प्रमुख के रूप में कार्यरत एक प्रमुख रूसी राजनयिक और राजनेता हैं

पेस्कोव के मुताबिक रूस, ईरान के नेतृत्व और खाड़ी के उन देशों के साथ लगातार संपर्क में है, जो इस बढ़ते तनाव से प्रभावित हो सकते हैं।

वहीं Russian Foreign Ministry ने अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की निंदा की है। साथ ही उसने राजनीतिक हत्याओं और संप्रभु देशों के नेताओं को निशाना बनाए जाने को भी गलत बताया है।

लेकिन असली सवाल अभी भी क़ायम है कि, क्या रूस और चीन सिर्फ कूटनीतिक बयान देंगे, या अगर टकराव बढ़ता है तो सचमुच ईरान के साथ खड़े भी होंगे ?

रविवार को Vladimir Putin ने Masoud Pezeshkian को संदेश भेजकर Ali Khamenei की हत्या पर संवेदना जताई और इसे 'मानवीय नैतिकता और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का गंभीर उल्लंघन' बताया था।

लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि इतनी कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद मॉस्को ने सीधे तौर पर Donald Trump की व्यक्तिगत आलोचना क्यों नहीं की। इतना ही नहीं, Russia अब भी United States को kraine युद्ध में मध्यस्थता की कोशिशों के लिए धन्यवाद देता दिखाई दिया।

सोमवार को जब Dmitry Peskov से पूछा गया कि ऐसी स्थिति में रूस अमेरिका पर भरोसा कैसे कर सकता है, तो उन्होंने कहा कि रूस 'सबसे पहले केवल खुद पर भरोसा करता है' और अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है।

रूस के इस रवैये से पता चलता है कि Iran के समर्थन में रूस की भूमिका फिलहाल ज़्यादातर कूटनीतिक बयानों तक ही सीमित रहेगी। हालाँकि आपको बता दें , Russian invasion of Ukraine के बाद ईरान, मॉस्को का अहम सहयोगी बना रहा है और तेहरान ने रूस को ड्रोन उपलब्ध कराए और पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के तरीकों में भी मदद की।

वहीं वैचारिक स्तर पर भी ईरान उस वैश्विक व्यवस्था की रूसी कल्पना से मेल खाता है, जिसमें दुनिया कई शक्तियों में बंटी हो, जहां मानवाधिकारों से ज्यादा महत्व राज्यों की संप्रभुता और सख्त सरकारी नियंत्रण को दिया जाए। ऐसे किसी शासन का पतन इस मॉडल के लिए बड़ा झटका माना जा सकता है।

लेकिन इन सबके बीच सवाल अब भी वही है क्या रूस का समर्थन केवल शब्दों तक सीमित रहेगा, या संकट गहराने पर वह वास्तव में ईरान के साथ खड़ा भी होगा? याद रहे Russia पहले भी कई मौकों पर यह संकेत दे चुका है कि वह अपने साझेदारों के लिए हद से ज़्यादा जोखिम उठाने से बचता है. चाहे मामला Venezuela का रहा हो, Syria का, या फिर 2025 में Israel और Iran के बीच चले 12 दिन के युद्ध का।

ऐसे में संकेत यही मिलते हैं कि मॉस्को शायद कूटनीतिक समर्थन और सीमित सैन्य-तकनीकी सहयोग से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है. या फिर उक्रैन जंग में मसरूफ होने की वजह से उसकी मजबूरी होगी।

इसके अलावा 17 जनवरी 2025 को रूस और ईरान के बीच हुई रणनीतिक साझेदारी की संधि भी पूर्ण रक्षा समझौता नहीं थी। इस समझौते में दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा करने, संयुक्त सैन्य अभ्यास करने और 'क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने' का वादा तो किया, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि यदि किसी एक पर हमला हो तो दूसरा उसकी रक्षा के लिए सैन्य रूप से आगे आएगा।

दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते भी सीमित ही रहे हैं और द्विपक्षीय व्यापार लगभग 4 से 5 अरब डॉलर के आसपास रहता है। हालांकि हाल के वर्षों में सैन्य और औद्योगिक सहयोग तेजी से बढ़ा है।

Financial Times की फरवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़े रक्षा समझौते के तहत रूस ईरान को करीब 500 मिलियन यूरो के Verba MANPADS देने की योजना बना रहा है। इसके अलावा ईरान को Yakovlev Yak-130 ट्रेनिंग विमान और Mil Mi-28 अटैक हेलिकॉप्टर मिल चुके हैं, जबकि वह Sukhoi Su-35 फाइटर जेट्स की भी उम्मीद कर रहा है। हालांकि वर्बा सिस्टम की आपूर्ति अभी तक नहीं हुई है।

यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर ईरान के Shahed drones ने रूसी सेना की रणनीति में बड़ा बदलाव लाया था। लेकिन पिछले साल मॉस्को ने अपने ड्रोन उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि कर ली, जिससे ईरानी हथियारों पर उसकी निर्भरता कम होती दिखाई दे रही है।

ऐसे में सवाल उठता है—मॉस्को के लिए ईरान की असली अहमियत क्या है? विश्लेषकों के मुताबिक रूस के लिए ईरान इतना महत्वपूर्ण जरूर है कि उसे पूरी तरह ढहने न दिया जाए, लेकिन शायद इतना भी महत्वपूर्ण नहीं कि उसके लिए सीधे युद्ध में कूड़ा जाए। जिस तरह अमेरिका इज़राइल के लिए कूद चूका है. यानी फिलहाल संकेत यही हैं कि रूस की भूमिका ज़्यादातर कूटनीतिक बयानबाज़ी और सीमित सैन्य सहयोग तक ही सिमटी रह सकती है।China ने भी रूस की तरह Ali Khamenei की हत्या की कड़ी निंदा तो की है। और बीजिंग लंबे समय से उस नीति का विरोध करता रहा है जिसे वह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में सरकारें बदलने की अमेरिकी कोशिश के तौर पर देखता है।

लेकिन यहाँ भी वही सवाल, क्या चीन का समर्थन सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा, या वह संकट की घड़ी में Iran के लिए जंग में कूदेगा ?

दरअसल चीन-ईरान रिश्ते की असली बुनियाद आर्थिक साझेदारी है। चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और उसका सबसे अहम ऊर्जा ग्राहक भी।

United States की लंबे समय से लागू सख्त पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान के लिए एक तरह की आर्थिक लाइफ़लाइन बना रहा है। वह बड़ी मात्रा में रियायती दरों पर ईरानी तेल खरीदता रहा है। यह तेल अक्सर तथाकथित 'घोस्ट फ़्लीट्स' के जरिए चीन तक पहुंचता है. यानी ऐसे जहाज़ जो झूठे रजिस्ट्रेशन या पहचान छिपाकर प्रतिबंधों से बचते हुए तेल ढोते हैं।

मसलन, 2025 में चीन ने ईरान के कुल निर्यातित तेल का 80 प्रतिशत से ज़्यादा खरीद लिया था। पश्चिमी बाज़ारों के लगभग बंद हो जाने के बावजूद, चीन से मिलने वाली इस आय ने ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था संभालने और रक्षा खर्च जारी रखने में बड़ी मदद दी।

साल 2021 में दोनों देशों के बीच हुई 25 साल की रणनीतिक साझेदारी की संधि ने इस रिश्ते को और मजबूत कर दिया। इस समझौते के तहत चीन ने ईरान के बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में सैकड़ों अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था।

लेकिन बड़ा सवाल वही ,क्या चीन अपने आर्थिक हितों से आगे बढ़कर ईरान के लिए कोई ठोस रणनीति या सैन्य जोखिम उठाने को भी तैयार होगा, या चीन का समर्थन भी कूटनीतिक बयानों तक ही सीमित रहेगा?

इतिहास बताता है कि China ने हमेशा Iran, Israel और nited States के बीच तनाव के मामलों में एक सावधानी भरी रणनीति अपनाई है। उदाहरण के तौर पर 2025 की गर्मियों में चले 12 दिन के इसराइल-ईरान युद्ध के दौरान बीजिंग ने लगातार 'संयम' की अपील की और हिंसा के लिए 'बाहरी हस्तक्षेप' को जिम्मेदार ठहराया. जिसे कई विश्लेषक अमेरिका की नीतियों की ओर इशारा मानते हैं।

पिछले टकरावों में चीन ने कई बार United Nations Security Council में ईरान के लिए कूटनीतिक ढाल का काम भी किया है . कभी वीटो लगाकर, तो कभी उसके संकेत भर से प्रस्तावों की भाषा नरम कराकर। लेकिन चीन ने कभी ईरान के समर्थन में सीधे सैन्य हस्तक्षेप का रास्ता नहीं चुना।

बीजिंग की रणनीति अक्सर इस तरह समझी जाती है, अमेरिका को मध्य पूर्व में उलझाए रखो, लेकिन इतना भी नहीं कि पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाए और तेल की कीमतें आसमान छूने लगें।

दरअसल, ईरान चीन के लिए सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर ईरान में पश्चिम समर्थित सरकार आ जाती है, तो यह बीजिंग के लिए बड़ा भू-राजनीतिक झटका हो सकता है, क्योंकि ईरान क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण संतुलन भी माना जाता है।

ईरान आज BRICS और Shanghai Cooperation Organisation दोनों का सदस्य है। साथ ही वह मध्य एशिया, कॉकसस और मध्य पूर्व को जोड़ने वाला एक अहम भूगोलिक पुल भी भी। ऐसे में इस्लामी गणराज्य की व्यवस्था का ढह जाना उन बहुपक्षीय ढांचों की विश्वसनीयता को भी झटका दे सकता है जिन्हें Russia और चीन मिलकर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर पूर्ण सैन्य हमला नहीं करते, तो संभावना यही है कि देश की राजनीतिक और सैन्य संरचनाएं किसी न किसी रूप में बनी रहेंगी।

ऐसी स्थिति में चाहे Ali Khamenei के बाद कोई भी नया नेतृत्व सामने आए, लेकिन बीजिंग अपने पुराने तरीक़े पर क़ायम रह सकता है. यानी लंबा खेल खेलना, यानी नए नेतृत्व के साथ रिश्ते बनाना और अपने आर्थिक-रणनीतिक हित सुरक्षित रखना।उधर मॉस्को की नीति भी कमोबेश इसी दिशा में दिखाई देती है, जहां Russia अपने हितों के अनुसार मौके तलाशता रहेगा, लेकिन सीधे युद्ध में उतरने से बचने की कोशिश करता रहेगा। ऐसे में खाड़ी के देशों की कूटनीति और राजनीती वहां की अवाम के निशाने पर नज़र आती है.

अगर अरब हुक्मरान इजराइल और अमेरिका की ग़ुलामी से बाज़ नहीं आते हैं और फलस्तीन व् ग़ज़ा की अवाम के अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं तो इस बात का इमकान है कि वहां की जनता ही अपने बादशाहों का तख़्ता पलट सकती है.

नाइजीरिया: बम धमाकों में लगभग 23 लोगों की मौत

नाइजीरिया में संदिग्ध श्रृंखलावार आत्मघाती बम धमाकों में लगभग 23 लोग मारे गए। देश के पूर्वोत्तर शहर मैदुगुरी की पुलिस ने आज बताया कि इस घटना में 100 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। ये धमाके कल शाम नाइजीरिया के अशांत बोर्नो प्रांत की राजधानी में हुए। फिलहाल, किसी भी समूह ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। पुलिस ने बताया कि एक धमाका व्यस्त मैदुगुरी बाजार में हुआ, दूसरा मैदुगुरी विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल-यूएमटीएच के गेट पर हुआ, जबकि तीसरा डाकघर के पास हुआ।

बलूचिस्तान: मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा हत्याएं और जबरन लापता होने की घटनाओं का किया खुलासा

बलूचिस्तान में हिंसा तेज होने के साथ ही प्रमुख मानवाधिकार संगठनों ने पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा दो लोगों की गैरकानूनी हत्या और अन्य लोगों के जबरन लापता होने की घटनाओं को उजागर किया है। ये घटनाएं प्रांत भर में गैरकानूनी हत्याओं और जबरन लापता होने की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई हैं। 4 मार्च को केच जिले में 26 वर्षीय दुकानदार हातुम बलूच की क्रूर हत्या हुई थी।

9 मार्च को खारान जिले में 24 वर्षीय मोहम्मद इस्माइल की हत्या पाकिस्तान समर्थित एक आतंकी दस्ते ने कर दी थी। मानवाधिकार संगठनों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संस्थाओं से तत्काल कार्रवाई करने और न्याय, सम्मान तथा स्वतंत्रता के लिए बलूलियों के संघर्ष में उनका साथ देने की अपील की। मानवाधिकार संस्था ने बलूच नागरिक इमदाद सैयद पर हुए क्रूर अत्याचारों की भी आलोचना की है।

इज़राइल के रक्षा मंत्री ने कहा- हवाई हमले में मारे गए ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी

इज़राइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने दावा किया है कि कल रात एक हवाई हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी मारे गए हैं। हालांकि, ईरान की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अली लारिजानी ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव थे।

उन्हें अगस्त 2025 में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रतिनिधि के रूप में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था। वे ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने 2008 से 2020 तक 12 वर्षों तक ईरान की संसद के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया।

इस बीच, इस्राएल की सेना ने दावा किया है कि उसने मध्य तेहरान में बासिज अर्धसैनिक बल के कमांडर गुलामरेज़ा सुलेमानी को भी मार गिराया है। खबरों के अनुसार, सुलेमानी वर्ष 2019 से बासिज सुरक्षा बलों के प्रमुख थे। ईरान की बासिज सेना में लगभग साढे चार लाख सुरक्षाकर्मी हैं।

पश्चिम एशिया में बग़दाद और दोहा सहित कई इलाकों में हवाई हमले

पश्चिम एशिया में आज इराक की राजधानी बगदाद और कतर की राजधानी दोहा सहित कई अन्य क्षेत्रों में हवाई हमले हुए। इससे क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। बगदाद में, अमरीकी दूतावास पर ड्रोन और रॉकेट हमले किए गए। इराक के अधिकारियों ने हमलों को रोकने की सूचना दी है। अल-रशीद होटल पर भी ड्रोन हमला हुआ, जबकि अल-जादिरिया में एक अन्य हमले में चार लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान समर्थित कताएब हिजबुल्लाह के एक कमांडर, अबू अली अल-अस्करी की मौत की खबरों के बाद तनाव और बढ़ गया है। इराक के प्रधानमंत्री, मोहम्मद शिया अल-सुदानी ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें आतंकवादी कृत्य बताया है। कतर ने ईरान से 14 बैलिस्टिक मिसाइलों और कई ड्रोन हमले किए जाने के बाद दोहा के ऊपर हवाई सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया गया है।

अमरीका ने हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ लगभग 57 अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते किए

अमरीका ने क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ लगभग 57 अरब डॉलर के ऊर्जा समझौते किए हैं। इन समझौतों को जापान में आयोजित पहले, हिन्द-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अंतिम रूप दिया गया। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में, अमरीका के आंतरिक सुरक्षा मंत्री, डग बर्गम ने कहा कि यह पहल राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प की सहयोगी देशों को ऊर्जा निर्यात बढ़ाने और अनिश्चित या राजनीतिक रूप से संवेदनशील स्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम करने की नीति का हिस्सा है।

लेबनान सीमा पर हिज़्बुल्लाह - इज़राइल संघर्ष तेज़, कई टैंक निशाना बने

बेरूत/तेल अवीव, (टॉप ब्यूरो) लेबनान-इज़राइल सीमा पर हिज़्बुल्लाह और इज़राइली सेना के बीच संघर्ष तेज हो गया है। मंगलवार को दोनों पक्षों के बीच भारी गोलीबारी और आमने-सामने की झड़पों की खबरें सामने आईं।

हिज़्बुल्लाह ने अपने ताज़ा बयान में दावा किया है कि उसने बाअलबेक क्षेत्र के तैय्यबा इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे इज़राइल के उन्नत मेरकावा टैंक को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। संगठन के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में यह पांचवां टैंक है जिसे उसके लड़ाकों ने तबाह किया है।

बताया जा रहा है कि यह घटनाक्रम नवंबर 2024 के संघर्षविराम समझौते के लगातार उल्लंघन के बाद सामने आया है। हिज़्बुल्लाह ने संकेत दिया है कि उसने अब अपनी 'संयम की नीति' समाप्त कर दी है और जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है।

इस बीच, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संबोधित करते हुए हिज़्बुल्लाह के प्रमुख शेख़ नाइं कासेम ने कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि धमकियों से संगठन पीछे हटने वाला नहीं है और लेबनान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा।

NOTICE:
Times of Pedia does not guarantee, directly or indirectly, the quality or efficacy of any product or services described in the advertisements or other material which is commercial in nature in this Newspaper. Furthermore, Times of Pedia assumes no responsibility for the consequences attributable to inaccuracies or errors in the printing of any published material from the news agencies or articles contributed by readers. It is not necessary to agree with the views published in this Newspaper. All disputes to be settled in Delhi Courts only.

The True Measure of Greatness: Valuing Human Life Above All

Najmuddin A Farooqi

The word great is used generously in our everyday language. We describe the universe as great, the oceans as great, the mountains and the skies as great. Even at a more modest level we apply the same word to countries, cities, monuments and sometimes even to a single tree or building.

Yet, despite its frequent use, the true meaning of greatness is rarely examined with seriousness. What, in reality, deserves to be called the greatest?

For those who believe in a divine order, the universe itself did not come into existence by chance but was created by a supreme Creator. The vastness of the cosmos the galaxies, stars, planets and oceans reflects the majesty of that creation.

However, within this magnificent universe there exists something far more remarkable, human life. Among all creations, the human being stands apart because of the unique gift of intellect, creativity and moral judgment.

If the Creator brought the universe and humanity into existence, it is the human mind that has shaped almost everything else that defines civilization. From prehistoric times, when early humans struggled merely to survive, to the dawn of organised societies and the evolution of great civilizations, it has been human wisdom that has cultivated progress.

Agriculture, architecture, philosophy, science and technology all are the fruits of human intellect. The modern world, with its advanced infrastructure, global communication systems and sophisticated medical science, is a testament to the extraordinary capabilities of the human mind.

Despite this remarkable journey, humanity often fails to recognize the true value of human life itself. Conflicts between nations are frequently explained as a "clash of civilizations" or a "clash of religions." Yet, in reality, they are neither.

At their core, most conflicts arise from a clash of human values differences in how societies respect dignity, justice and the sanctity of life. When these values weaken, violence and confrontation take their place.

In this regard, some societies have demonstrated a deeper institutional respect for individual human life. The United States, for instance, is widely regarded as one of the oldest and most robust modern democracies, where civil liberties and individual rights are strongly emphasised.

One of the most striking features of that society is the respect shown to every citizen, particularly to those who sacrifice their lives in service to the nation. When soldiers are killed in war, the solemn tributes paid to them reflect a deep cultural recognition of the value of each individual life.

This raises an important question: why is America so frequently criticised across the world ? Is it because of its prosperity, its vast natural resources, or its technological and scientific leadership ? In many areas especially science, technology and medical research the United States remains far ahead of most other nations.

Its institutions have contributed immensely to global progress, producing life-saving drugs, advanced medical equipments and scientific innovations that benefit people far beyond its borders.

Yet the real issue may lie elsewhere. Americans, like people in many other societies, believe in God and in moral accountability. However, the difference often lies in attitudes toward effort and responsibility. In many parts of the world, complacency prevails, what is easily achieved is considered sufficient and further effort is left to fate or divine will. Progress, however, rarely comes through complacency. It comes through persistent effort, curiosity and the relentless pursuit of knowledge.

Imitation for its own sake is not admirable, but learning from others certainly is. Nations that seek knowledge, discipline and innovation will inevitably progress. Only then can they engage with the world with dignity and confidence, rather than with resentment or insecurity.

Ultimately, the highest form of greatness lies in respecting human life everywhere, not only within national borders but across them. Perhaps the world will move closer to that ideal when every society is guided by leaders who embody compassion, moral courage and humility figures reminiscent of Mahatma Gandhi, who placed the value of human life above political power.

Healthy criticism is neither inappropriate nor unwarranted, particularly when directed at the conduct of political leadership rather than the people of a nation. In the present context, the concern is not with the American public but with President Trump perceived as bringing a distinctly commercial temperament into the realm of governance accompanied by confrontational rhetoric. In second term his approach has increasingly shaped an assertive and unpredictable foreign policy.

His unwavering support for the Israel president Netanyahu during the ongoing tensions and conflict involving US Israel and Iran has further intensified regional anxieties.

Actions such as the dramatic handling of political leadership in Venezuela and the reported targeting and killing of Iran's Supreme Leader and other high ranking officials have been widely viewed as deeply controversial.

These developments are the serious challenges to the principles of sovereignty and the norms that govern relations among nations.

While debate and criticism are essential in international politics, these events have raised profound questions about restraint, accountability and long term implications of power politics in an already fragile global order.

In the end, the greatness of nations, civilisations, or leaders will not be measured by their power or wealth, but by the degree to which they honour the most precious creation in the universe, human life.

Imperialism Bares its Claws, yet again: Iran Attacked

Prof. Ram Puniyani

The joint attack ot Israel and America on Iran has been very devastating. Like most wars it is brutal to the core. The pretext of the war has been that Ayatollah Khamanei regime has been very brutal, against women's rights and preparing nuclear weapons. Iran in turn was willing to be on the negotiating table and willing to concede some of the points emerging from the talks. In the middle of talks Israel-America(I-A) axis decided to launch the war and in the initial part of the war it inflicted to severe damages to Iran. One was the killing of Khamanei along with some of his family members and the other was bombing of a school in which 165 young girls lost their lives. Many a civilian have also been targeted by the I-A axis. Also, a naval ship of Iran which had arrived in India on India's invitation for Naval exercises was torpedoed by the US submarine killing large number of sailors on the ship. Iran bravely retaliated and caused huge damage to I-A axis.

During this India's role during all these happenings is a great eye-opener; about its evolving foreign policy. India was non aligned to begin with, having very amicable relations with Iran. The cultural and economic exchanges between the two countries was excellent. Now we see that Indian Prime Minister Modi visited Israel, just before the war. The goal of the visit was unknown to the country. He did receive the highest honour of Israel and pledged that India will be with Israel in its thick and thin. The day next, I-A attacked Iran. Mr. Modi did not tweet about the demise of the Iran's supreme leader and also issued a blank statement equating the aggressor and the aggrieved county. The transition of India from and neutral to embracing the American-Israel axis came out louder with the acts of commission and omission of Indian Prime Minster.

Back to American story. We have been watching the role of U.S. particularly from 1950s. The role has been that of interfering in other countries affairs for its political and economic goals. Earlier 'saving the world from Communism' has been its major plank for unleashing wars, starting from the Vietnam war. As French had colonised Vietnam and the Ho Chi Minh's communist army overthrew the French, a long and complicated political process led to division of Vietnam along 17th parallel into Communist North Vietnam and Capitalist South Vietnam. Americal launched a horrific war against Vietnam, spending millions of dollars. The Americans used chemical weapons Napalm (jellied petrol) and Agent Orange (superior strength weed killer). This was used to clear foliage in the jungle which was the natural hiding place for the Vietcong (army raised by Vietnamese). Napalm did clear much of the undergrowth but it also stuck to humans and caused horrific injuries. Agent Orange also killed many innocent civilians' farms, crops were lost and animals were killed.

The Vietnamese people were more for Ho Chi Minh. Viet Cong through Gorilla tactics came victorious and America for once had to face the defeat, its army over five lakhs strong retreated with its morale crushed by the defeat at the hands of a new and young Nation. This Vietnam war showed abundantly that America is not going to spare any efforts to defeat those who are against its interests presented as the ideology of 'Free World".

This became clearer in due course as America attacked country after country on one or the other pretext. The second major case was that of Iran. With its strategic location and vast oil reserves, Iran was of special interest to the Western powers, United States, the United Kingdom in the main. Britain was the major power to have its presence in Iran during the World War II. After the war, the England continued to retain its control over Iran's oil through the establishment of the Anglo-Iranian Oil Company. It was exploiting Iran's oil for its own interests. This arrangement changed abruptly in 1951 when the Iranian parliament, led by Mosaddegh's nationalist and democratically elected government, voted to nationalize the country's oil industry. From here Britain started opposing Mossadegh regime and tried to foment opposition to him. Britain took along America and a coup was staged in Iran uprooting the democratically elected Government and installing Raza Shah Pehlavi, a stooge of America. Oil interests in the hands of Western powers remained safe for them.

The story of Salvador Allende's elimination and overthrowing of a democratic Government in Chile are fairly similar. Allende was a Marxist, a member of Socialist party. Allende was sworn in on Nov. 3, 1970 as President of Chile. He decided to nationalize Copper companies controlled by America in particular. U.S. spent $8 million on covert actions between 1970 and the 1973 coup. According to a 1975 Senate report. U.S. officials also backed economic measures to squeeze Allende's government. In a CIA supported Coup the military dictator Pinochet came to power. He was very ruthless and wrought havoc on the democracy and potential prosperity of Chile.

The harm inflicted on West Asia was much more dangerous. After USSR occupation of Afghanistan, America supported some Madarassas in Pakistan and helped training Mujahids. From this Taliban; Al Qaeda were formed. America funded them to the extent of 8 thousand million dollars and supplied them with 7 thousand tons of armaments (Mahmood Mamdani's book: Good Muslim-Bad Muslim'). After 9/11 America got the pretext to attack Afghanistan in which 60000 people were killed. To dominate the whole region, it came up with the pretext of 'Weapons of Mass destruction' to attack Iraq. The soldiers were told that Iraq's people are being oppressed by Saddam Hussian, so this war is needed. They were also told that the people will see you as the liberators and you will be welcomed with bouquets and chock lets. Something else happened and Iraq was dismantled with rise of Islamic State. Neither weapons of mass destruction could be located nor American soldiers were welcomed.

Colonialism and Imperialism leave dangerous marks on the victim countries and the World as a whole. In India British policy of 'divide and rule' led to the strengthening of communal forces, the ills of which we are suffering till date. American Media's coining and popularising the phrase 'Islamic terrorism' has led to the global demonization of Muslims. Both these phenomenon, Colonialism and Imperialism have been the forces at the roots of major problems which the world is facing today. Hope we can promote peace by realizing the impact of Impeiralism.

"सोनम वांगचुक की रिहाई लोकतंत्र की जीत"

Maroof Raza Senior Journalist

सोनम वांगचूक की रिहाई लद्दाख के संघर्ष और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटना है। उनकी रिहाई लद्दाख की आवाज़ और न्याय की जीत है।

मैं बात कर रहा हूं लद्दाख की उस बुलंद आवाज़ की, जिसने हिमालय की बर्फीली चोटियों से निकलकर पूरे देश के दिल में जगह बनाई। मैं बात कर रहा हूं मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की।

करीब 170 दिनों के लंबे इंतजार के बाद, केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। 14 मार्च 2026 को उन्हें जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया। यह रिहाई केवल एक व्यक्ति की आज़ादी नहीं है, बल्कि लद्दाख के उन हज़ारों लोगों की उम्मीदों की जीत है, जो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।मामला सितंबर 2025 का है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की 'छठी अनुसूची' में शामिल करने की मांग को लेकर लेह में आंदोलन चल रहा था। इसी दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें दुर्भाग्यवश चार लोगों की जान चली गई। प्रशासन ने सोनम वांगचुक पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए उन पर कड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगा दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

वांगचुक की रिहाई के पीछे एक लंबी कानूनी लड़ाई भी रही है। उनकी पत्नी, डॉ. गीतांजलि अंगमो, ने सुप्रीम कोर्ट में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' (Habeas Corpus) याचिका दायर की थी। अदालत ने सरकार से वांगचुक के बयानों का सटीक अनुवाद मांगा और उनकी हिरासत पर सवाल उठाए। आखिरकार, सरकार ने स्वीकार किया कि वांगचुक अपनी हिरासत अवधि का लगभग आधा समय पूरा कर चुके हैं और लद्दाख में शांति और संवाद का माहौल बनाने के लिए उन्हें रिहा करना ज़रूरी है।

वांगचुक की रिहाई का लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने स्वागत किया है। उन्होंने इसे एक बड़ी जीत बताया और कहा कि अब उनके आंदोलन पर लगा 'देशद्रोही' का टैग हट गया है। हालाँकि, लद्दाख की मांगें अभी भी जस की तस ही हैं।

सोनम वांगचुक की रिहाई हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र में संवाद ही सबसे बड़ा रास्ता है। क्या यह रिहाई लद्दाख की समस्याओं का स्थायी समाधान लाएगी? यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज लद्दाख की आवाज़ फिर से स्वतंत्र है।

SUBSCRIPTION FORM
TIMES OF PEDIA

Issue	Subscription Price	Years
52	250/-	1
104	500/-	2
260	1,300/-	5
520	2,600/-	10
--	5,000/-	Life

Name :.....
Address :.....
.....
.....
Email:.....
Contact Phone No.....
for donation ☐ /life ☐ /10 yrs ☐ /5 yrs ☐ subscription
The sum of Rupees..... (Rs...../-)
through cheque/DD No.....dt.....

Fill the above form neatly in capital letters and send it to us on the following address :
Times of Pedia, K-2-A-001, Abul Fazal Enclave-I, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi-110025
or email : **timesofpedia@gmail.com**

Also Send us your subscription, membership, donation amount in favour of Times of Pedia, New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch,
New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

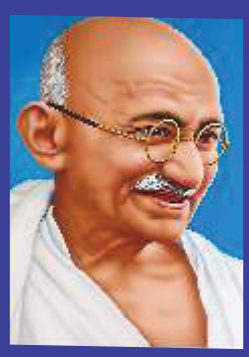

"First, they ignore you, then they laugh at you, then they fight you and then you win."
- Mahatma Gandhi

ADVERTISEMENT TARIFF
TIMES OF PEDIA

Size/Insertion Single	B&W (Rs)	4 Colour (Rs)
Full Page (23.5 x 36.5 cm)	30,000/-	1,00,000/-
A4 (18.7 x 26.5 cm)	20,000/-	60,000/-
Half Page (Tall-11.6 x 36.5 cm)	18,000/-	50,000/-
Half Page (wide-23.5 x 18 cm)	8,000/-	50,000/-
Quarter Page (11.6 x 18 cm)	10,000/-	28,000/-
Visiting Card size (9.5 x 5.8 cm)	3,000/-	10,000/-

MECHANICAL DATA:

Language: English, Hindi and Urdu

Printing: Front and Back - 4 Colours , Inside pages - B&W

No. of Pages: 12 pages (more in future)

Price: Rs. 3/-

Print order: 25,000

Periodicity: Weekly

Material details: Positives/Format of your advertisements should reach us 10 days before printing.

Note: 50% extra for back page, 100% extra for front page

Please Add Rs. 10 for outstation cheques.

50% advance of total add cost would be highly appreciable, in case of one year continue add. Publication cost will reduce 50% of actual cost.

Bank transactions details of TIMES OF PEDIA
Send your subscriptions/memberships/donations etc. (Cheques/DD) in favour of TIMES OF PEDIA New Delhi
Punjab National Bank,Nanak Pura Branch , New Delhi-110021
A/C No.1537002100017151, IFS Code : PUNB 0153700

रोटी का आटा गूंथने का सही तरीका: पानी की मात्रा और टिप्स

नई दिल्ली,(टॉप ब्यूरो) भारत में रोटी न केवल भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बल्कि यह कई परिवारों के दैनिक खाने में अनिवार्य रूप से शामिल होती है। अधिकतर घरों में रोटियां गेहूं के आटे से बनाई जाती हैं। हालांकि, कई बार देखा गया है कि खासकर अकेले रहने वाले लड़के-लड़कियां या नए घर में रहने वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि आटा गूंथते समय कितना पानी डालना सही रहेगा और कब रोटियां बेलनी चाहिए।

रोटी बनाना सरल कार्य लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक परफेक्ट रोटी वह होती है जो सॉफ्ट, फूली हुई और बेलने में आसानी वाली हो। अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग, जो हॉस्टल या नए घर में रहते हैं, रोटियां बनाने में परेशानी का सामना करते हैं। कई बार उनकी रोटियां ठंडी होने पर पापड़ जैसी सख्त हो जाती हैं या बेलते समय चकले और बेलन पर चिपक जाती हैं।विशेषज्ञों और अनुभवी शेफों के अनुसार, इसका मुख्य कारण है कि आटा सही तरह से गूंथा नहीं गया होता। आटे में पानी की मात्रा, उसके गूंथने की तकनीक और गुनगुने पानी का इस्तेमाल, इन सबका सीधा असर रोटी की गुणवत्ता पर पड़ता है।

शेफ और बावर्चियों का कहना है कि आटे का परफेक्ट डो बनाने के लिए पानी की मात्रा आटे की क्वालिटी पर निर्भर करती है। सामान्यत: 2 कप गेहूं के आटे के लिए लगभग 1 कप से थोड़ा कम पानी पर्याप्त होता है। इसका मतलब है कि आटे और पानी का अनुपात लगभग 2:1 होना चाहिए।

लेकिन इस नियम में भी कुछ लचीलापन होता है। अगर आटा मोटा है या पुराना है, तो यह अधिक पानी सोख सकता है। ऐसे में थोड़ी मात्रा में अतिरिक्त पानी डालना उचित होगा। वहीं, अगर आटा बहुत नरम या नया है, तो पानी की कम मात्रा से भी पर्याप्त नरमी प्राप्त की जा सकती है।

घर पर बिना मशीन और केमिकल के बनाएं स्वादिष्ट किशमिश

नई दिल्ली, (टॉप ब्यूरो) अगर आप बाजार से महंगी किशमिश खरीदने से परेशान हैं, तो अब इसका आसान और प्राकृतिक विकल्प आपके पास है। घर पर अंगूर से बिना मशीन और केमिकल के, केवल धूप की मदद से स्वादिष्ट और हेल्दी किशमिश तैयार की जा सकती है। यह न केवल सस्ती होती है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।

ड्राई फ्रूट्स भारतीय घरों का अहम हिस्सा हैं। बादाम, काजू और किशमिश से लेकर कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स न केवल मिठाइयों का स्वाद बढ़ाते हैं, बल्कि पोषण भी प्रदान करते हैं। किशमिश विशेष रूप से खीर, हलवा या किसी भी मिठाई में डालने से उसका स्वाद कई गुना बढ़ा देती है। यह बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आती है।

हालांकि, अच्छी क्वालिटी की किशमिश बाजार में अक्सर काफी महंगी होती है, जिससे रोजाना खरीदना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में घर पर अंगूर से बनी किशमिश एक किफायती और प्राकृतिक

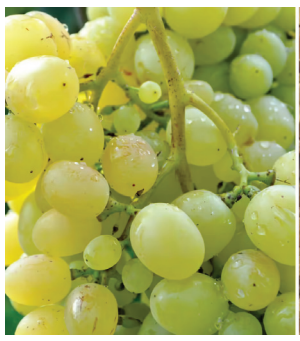

विकल्प है। इसमें किसी भी तरह के रसायन या मशीन का इस्तेमाल नहीं होता, और यह पूरी तरह से नेचुरल होती है।

घर पर किशमिश बनाने के लिए सबसे पहले सही अंगूर चुनना जरूरी होता है। अंगूर जितने मीठे होंगे, किशमिश उतनी ही मीठी और स्वादिष्ट बनेगी। अंगूर का सीजन होने के कारण बाजार में यह आसानी से सस्ते दामों में मिल जाते हैं, इसलिए यह तरीका काफी किफायती भी साबित होता है। अंगूर को अच्छी तरह धोकर अतिरिक्त पानी पोंछ लें और उन्हें धूप में फैलाकर सुखाएं। तेज धूप में अंगूर धीरे-धीरे सिकते हैं और उनका पानी सूख जाता है। इस प्रक्रिया में लगभग सात से दस दिन का समय लगता है। बीच-बीच में अंगूर को पलटते रहें ताकि सभी अंगूर समान रूप से सूख जाएं। जब अंगूर पूरी तरह सूख जाएं और उनका रंग गहरा हो जाए, तब उन्हें किसी बर्तन में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी प्रक्रिया के बाद आपकी घर की बनी प्राकृतिक किशमिश तैयार हो जाती है।

घर पर बनी किशमिश बाजार की तुलना में काफी सस्ती, प्राकृतिक और हेल्दी होती है। यह बच्चों और बड़ों के लिए स्वादिष्ट स्नैक्स के रूप में भी काम आती है और मिठाइयों में डालने से उनका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। घर पर अंगूर से बनी किशमिश बनाने के लिए केवल धूप, सही अंगूर और थोड़ा धैर्य चाहिए। इस सरल और प्राकृतिक तरीके से आप रोजाना ताजी और स्वादिष्ट किशमिश का आनंद ले सकते हैं, बिना महंगे दाम चुकाए।

इस तरह, घर पर अंगूर से बनी किशमिश बनाना न केवल सस्ती और हेल्दी है बल्कि यह स्वाद और पोषण का सही मिश्रण भी प्रदान करती है। इसे बनाने के लिए बस सही अंगूर, धूप और थोड़ी धैर्य की जरूरत होती है। इस प्राकृतिक और आसान तरीके से आप रोजाना ताजी और स्वादिष्ट किशमिश का आनंद ले सकते हैं, बिना महंगे दाम चुकाए। इसके अलावा, घर पर बनी किशमिश की एक बड़ी खासियत यह है कि आप पूरी तरह से केमिकल-फ्री विकल्प का चयन कर रहे हैं। बाजार की किशमिश में अक्सर सुरक्षा और रंग बनाए रखने के लिए केमिकल या प्रिज़र्वेटिव इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि घर पर बनी किशमिश पूरी तरह से प्राकृतिक रहती है। इस वजह से यह छोटे बच्चों, बुजुर्गों और स्वास्थ्य के प्रति सजग लोगों के लिए सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बन जाती है।

घर पर बनी किशमिश को आप विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं।

खेल समाचार

पीएसएल 11 से पहले विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा पर पीसीबी ने तोड़ी चुप्पी

लाहौर, (टॉप ब्यूरो) पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के ग्यारहवें सीजन को लेकर विदेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा और यात्रा को लेकर उठ रहे सवालों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने साफ किया है कि सभी इंतजाम पूरे हैं और कोई परेशानी नहीं होगी।

पीसीबी ने स्पष्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों सहित सभी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तय समय पर टूर्नामेंट में शामिल होंगे। बोर्ड ने कहा कि मध्य पूर्व में तनाव और अफगानिस्तान सीमा के हालात के बावजूद पीएसएल 11 निर्धारित तारीखों पर, 26 मार्च से लाहौर में शुरू होगा।

सूत्रों के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अगले सप्ताह से पाकिस्तान पहुंचना शुरू करेंगे। पीसीबी ने भरोसा दिलाया कि लीग पहले भी चुनौतियों का सामना कर चुकी है और इस बार भी यह बिना किसी बाधा के आयोजित होगी।

इस सीजन में स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर, एडम जाम्पा, पीटर सिडल, आरोन हार्डी, मार्नस लाबुशेन, एश्टन टर्नर, जेक फ्रेज़र-मैकगर्क, जोश फिलिप, रिले मेरेडिथ और बेन मैकडरमॉट जैसे बड़े नाम खेलेंगे।

पीएसएल 11 कई मायनों में खास होने जा रहा है। इस बार आठ टीमें भाग लेंगी, और टूर्नामेंट आईपीएल से तीन दिन बाद शुरू होगा। पीसीबी का भरोसा है कि सभी परिस्थितियों के बावजूद पीएसएल 11 सफल और प्रतिस्पर्धी होगा।

कुलदीप यादव का लखनऊ में भव्य रिसेप्शन, सीएम योगी समेत कई दिग्गज मौजूद

टीम इंडिया के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव की शादी के बाद मंगलवार को लखनऊ के होटल द सेंट्रम में उनका भव्य रिसेप्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में क्रिकेट और राजनीति की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं। कुलदीप यादव ने 14 मार्च को अपनी बचपन की दोस्त वंशिका सिंह से शादी की थी। यह शादी उत्तराखंड के हिल स्टेशन मसूरी में परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में संपन्न हुई थी। रिसेप्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और उन्होंने कुलदीप व वंशिका को आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही उन्होंने क्रिकेटर के परिवार के सदस्यों के साथ फोटो खिंचाई। इस कार्यक्रम में भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, पूर्व ओपनर शिखर धवन और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपनी पत्नियों के साथ शामिल हुए। खिलाड़ियों का स्वागत फूलों की बारिश के साथ किया गया। रिसेप्शन में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी उपस्थित रहे।

روزہ اور صبر کی تعلیم

بنتِ ابوالخیر اعظمی

رمضان المبارک کا مقدس مہینہ انسان کی روحانی تربیت، اخلاقی تطہیر اور باطنی اصلاح کا عظیم ذریعہ ہے۔ اس ماہِ مبارک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت، توبہ، صبر اور شکر کے نور سے منور ہونے کا خاص موقع عطا فرماتا ہے۔ روزہ دراصل صرف بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک جامع عبادت ہے جو انسان کو صبر، برداشت، ضبطِ نفس اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتی ہے۔ روزہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے جس کی فرضیت کا ذکر مقدس کتاب القرآن الکریم میں اس طرح آیا ہے کہ روزہ انسان کو تقویٰ کی روش پر گامزن کرتا ہے۔ روزہ رکھنے والا شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنی خواہشات کو محدود کر لیتا ہے اور نفس کی سرکشی پر قابو پانا سیکھتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر صبر کی وہ قوت پیدا کرتا ہے جو زندگی کی مشکلات میں اسے ثابت قدم رکھتی ہے۔ صبر انسانی زندگی کا سب سے حسین اور طاقتور وصف ہے۔ صبر کا مطلب صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے حالات کا سامنا کرنا ہے۔ روزہ انسان کو یہی سبق دیتا ہے کہ جب وہ حلال کھانے پینے کو بھی ایک مقررہ وقت تک چھوڑ سکتا ہے تو پھر وہ حرام اور ناپسندیدہ اعمال سے کیوں نہیں بچ سکتا۔ اس طرح روزہ نفس کی اصلاح کا بہترین مدرسہ ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا ماحول انسان کے دل کو نرم اور روح کو بیدار کرتا ہے۔ جب روزہ دار بھوک اور پیاس کی شدت محسوس کرتا ہے تو اسے غریب اور محتاج انسانوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اس احساسِ ہمدردی سے معاشرے میں محبت، اخوت اور بھائی چارے کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ روزہ دراصل انسان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے جینا سیکھے۔ صبر کی تعلیم روزے کا ایک عظیم پیغام ہے۔ زندگی میں مشکلات، بیماری، غربت اور آزمائشیں انسان کا امتحان ہوتی ہیں۔ روزہ دار جب اللہ کی خاطر صبر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو ذہنی سکون اور قلبی اطمینان عطا کرتا ہے اور اس کے دل کو نورِ ایمان سے روشن کرتا ہے۔ روزہ انسان کو اخلاقی بلندی بھی عطا کرتا ہے۔ روزہ دار کو غیبت، جھوٹ، لڑائی جھگڑے اور بدزبانی سے بچنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی اخلاقی برائیوں میں مبتلا رہے تو اس کا روزہ روحانی اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا۔ روزہ انسان کی زبان، نگاہ اور دل سب کو پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ روزہ انسان کے اندر شکرگزاری کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کچھ دیر کے لیے اپنی پسندیدہ چیزوں سے دور رہتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ پانی کا ایک گھونٹ اور روٹی کا ایک لقمہ بھی اسے اللہ کی عظیم نعمت محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی احساس انسان کو ناشکری سے بچاتا ہے اور شکر کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ صبر اور روزہ دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ روزہ صبر کی عملی تربیت ہے اور صبر ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ جو انسان روزے کی حالت میں اپنے نفس پر قابو رکھتا ہے وہ زندگی کے دیگر معاملات میں بھی ضبطِ نفس کی دولت حاصل کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کو روحانی اصلاح کا موسمِ بہار کہا جاتا ہے۔ روزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت عطا کرتا ہے کیونکہ روزہ خاص طور پر اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ خود عطا فرماتا ہے۔ روزہ دار جب سحر و افطار کے درمیان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کا دل نورِ ایمان سے روشن ہو جاتا ہے۔ صبر کی یہی کیفیت انسان کو روحانی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ روزہ صرف ایک عبادت نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ روزہ انسان کو صبر، برداشت، اخلاق، ہمدردی اور تقویٰ کی اعلیٰ تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص رمضان کے پیغام کو سمجھ لے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقی روح سمجھنے، صبر کی دولت حاصل کرنے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

انسانی حقوق: خواتین کے حقوق میں تشویشناک تنزلی

مدیحہ فصیح

آج کی دنیا جہاں ایک طرف مصنوعی ذہانت، خلائی تسخیر اور ٹیکنالوجی کی برق رفتار ترقی کے گن گا رہی ہے، وہیں دوسری طرف انسانی حقوق کے حوالے سے ایک ہولناک عالمی پسپائی کا منظرنامہ ابھر رہا ہے۔ تمام خواتین اور لڑکیوں کے لیے انصاف تک رسائی کو یقینی بنانا اور اسے مضبوط بنانا کے عنوان سے اقوام متحدہ کی 2026 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح خواتین کی آزادیوں کو محدود کرنے، ان کی آواز کو خاموش کرنے اور بغیر کسی سزا کے بدسلوکی کی اجازت دینے کے لیے قوانین کی تشکیل نو کی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ اس تلخ تضاد کو بے نقاب کرتی ہے کہ معاشی اور سائنسی ترقی کے دعووں کے برعکس، خواتین کے بنیادی حقوق میں عالمی سطح پر ایک ایسی تنزلی دیکھی جا رہی ہے جو دہائیوں کی جدوجہد کو ملیا میٹ کر سکتی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں اس بنیادی سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا ہمارا موجودہ "انصاف کا نظام" واقعی سب کے لیے برابر ہے، یا یہ اب بھی صرف طاقتور کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ عالمی سطح پر صنفی مساوات کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر میں خواتین کو مردوں کے مقابلے میں اوسطاً صرف 64 فیصد قانونی حقوق حاصل ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 70 فیصد ممالک میں خواتین اور لڑکیوں کو انصاف کے حصول میں مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اسے ماہرین انصاف کا خلا قرار دے رہے ہیں۔ جب قانونی ڈھانچے ہی غیر مساوی ہوں، تو وہاں انصاف کی فراہمی ایک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک لرزہ خیز حقیقت یہ ہے کہ 54 فیصد ممالک کے قوانین میں اب بھی عصمت دری کی تعریف میں رضامندی" کا تصور شامل نہیں ہے، جو مجرموں کو قانون کی گرفت سے بچ نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ ڈائریکٹر، یو این ویمن کی ڈائریکٹر سارہ ہینڈرکس کے مطابق، جہاں طاقت غیر مساوی رہتی ہے، انصاف شاذ و نادر ہی غیر جانبدارانہ کام کرتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صنفی مساوات سے پسپائی واضح طور پر نظر آنے لگتی ہے۔ عالمی تنازعات کی بڑھتی ہوئی لہر خواتین کی زندگیوں کو براہِ راست نشانہ بنا رہی ہے۔ 2024 کے اعداد و شمار کے مطابق، تقریباً 67 کروڑ 60 لاکھ خواتین اور لڑکیاں مہلک جنگی علاقوں کے محض 50 کلومیٹر کے دائرے میں زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، جو کہ 1990 کی دہائی کے بعد اب تک کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ان جنگی حالات میں جنسی تشدد کو محض ایک اتفاقی نتیجہ نہیں بلکہ ایک باقاعدہ "جنگی ہتھیار" کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یو این ویمن کی رپورٹ کے مطابق، تنازعات سے وابستہ جنسی تشدد کے واقعات میں 87 فیصد تک ہوش ربا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ان جرائم میں ملوث افراد کے لیے سزا سے استثنیٰ" کا کلچر عام ہے، جو اس وحشتناک چکر کو مزید تقویت دیتا ہے۔ خواتین کو تحفظ فراہم کرنے والا ادارہ جاتی ڈھانچہ تیزی سے بکھر رہا ہے۔ جب کسی متاثرہ خاتون کے لیے انصاف کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو اس کا اثر صرف ایک فرد تک محدود نہیں رہتا بلکہ معاشرے کا اداروں پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، خواتین پر تشدد کے خلاف کام کرنے والی تقریباً 90 فیصد تنظیموں نے مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے اپنی بنیادی خدمات میں کٹوتی کی ہے۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ صرف 5 فیصد تنظیمیں ہی یہ یقین رکھتی ہیں کہ وہ موجودہ حالات میں اگلے دو سال تک اپنا کام جاری رکھ سکیں گی۔ یہ اعداد و شمار محض نمبر نہیں ہیں؛ یہ اس بات کی علامت ہیں کہ تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کے لیے وہ آخری پناہ گاہیں بھی ختم ہو رہی ہیں جہاں سے انہیں مدد کی امید تھی۔ سارہ ہینڈرکس کے بقول، جب انصاف خواتین کو ناکام بناتا ہے تو عوامی اعتماد پامال ہوتا ہے اور انصاف کے اداروں کا اخلاقی جواز ختم ہو جاتا ہے"۔ مایوسی کے ان بادلوں میں امید کی کرن صرف ان اصلاحات سے وابستہ ہے جو "خواتین کے ذریعے اور خواتین کے لیے" ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ 1970 سے اب تک خاندانی قوانین میں کی جانے والی اصلاحات کی بدولت 60 کروڑ سے زائد خواتین کو معاشی مواقع تک رسائی حاصل ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق، وولکر ترک، اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مستقبل کی پالیسیوں میں پدرانہ سوچ (پیٹریارکی) کو چیلنج کرنا لازمی ہے۔ ان کے مطابق، پدرانہ نظام دراصل معاشرے کے ہر فرد کے لیے نقصان دہ ہے۔ وولکر ترک تجویز کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے خصوصی اقدامات کی ضرورت ہے جو نہ صرف خواتین کی قیادت کو فروغ دیں بلکہ مردوں اور لڑکوں کو بھی اس بات کی تربیت دیں کہ صنفی برابری ہی پرامن اور مستحکم معاشرے کی بنیاد ہے۔ خواتین کی مکمل شرکت سے نہ صرف امن معاہدے زیادہ پائیدار ہوتے ہیں بلکہ کاروباری ادارے بھی زیادہ منافع بخش ثابت ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کی عالمی تنزلی محض ایک سماجی مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک تہذیبی بحران ہے۔ اگر ہم نے آج انصاف کے ان خلاؤں کو پُر نہ کیا، تو ہم ایک ایسی دنیا کی طرف لوٹ جائیں گے جہاں طاقت ہی حق تسلیم کی جاتی ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب تک آدھی آبادی قانون کے سامنے برابر نہیں ہوگی، حقیقی عالمی ترقی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ کیا ہم واقعی ایک ایسی دنیا کے متحمل ہو سکتے ہیں جہاں آدھی انسانیت کو انصاف کے بنیادی حق سے محروم رکھ کر ترقی کا سفر جاری رکھا جائے؟ اس پر غور و فکر کی ضرورت ہے۔

आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण का विस्तार किया

आयुष मंत्रालय ने आयुष ग्रिड के तहत आयुष अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली (एएचएमआईएस) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं, ताकि चिकित्सकों और फार्मासिस्टों द्वारा आयुष केंद्रों में दवाओं की उपलब्धता का डिजिटलीकरण और निगरानी की जा सके।

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को आयुष पद्धति के सामर्थ्य के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण (बीसीसी) और सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। इन पहलों में आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल पद्धतियों को बढ़ावा देने और समुदायों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु जनसंचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, व्यवस्थित आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न जनसंपर्क गतिविधियों को भी समर्थन दिया जा रहा है, जिनका उद्देश्य शिविरों का आयोजन करके समाज को जागरूक करना और अन्य आयुष स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ उचित रेफरल लिंकेज के माध्यम से आयुष पद्धतियों की सामर्थ्य का उपयोग करते हुए सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। इसके द्वारा एकल उपचारों के रूप में अथवा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के पूरक के रूप में

निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

एनएएम के तहत, देश भर में 12,500 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (आयुष) [एएएम (आयुष)] को कार्यशील किया गया है। आयुष मंत्रालय ने आशा और एनएएम कर्मियों सहित स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने और रोगों की रोकथाम के लिए आयुष के लाभों के बारे में प्रशिक्षित करने हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम आयोजित किया है। ये जमीनी स्तर के कर्मी एएएम (आयुष) से जुड़े हुए हैं और समाज को जागरूक करने तथा सामान्य बीमारियों के लिए आयुष पद्धतियों का उपयोग करके आसान निवारक स्वास्थ्य देखभाल प्रथाओं पर लोगों का मार्गदर्शन करने में लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सीएचईबी), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत) के सहयोग से, वर्ष ख्ख और ख्ख में आयुष चिकित्सा पद्धतियों में मस्कुलोस्केलेटल और चयापचय संबंधी विकारों के प्रबंधन पर मास्टर प्रशिक्षक कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा अधिकारियों के लिए आयोजित किए गए थे, जिनमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। इसके अलावा, एनएएम के लचीले घटक के तहत, शिक्षण संस्थानों और आयुष अस्पतालों/औषधालयों में शिक्षण कर्मियों, चिकित्सा अधिकारियों और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारें एनएएम दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) के माध्यम से उपयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करके वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष मंत्रालय एक केंद्रीय क्षेत्र योजना नामत: आयुर्ज्ञान को भी कार्यान्वित कर रहा है, जिसमें आयुष कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) के घटक के तहत वित्तीय सहायता का प्रावधान है। भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के समन्वय से एनएएम योजना कार्यान्वित कर रही है और विभिन्न आयुष पद्धतियों की सामर्थ्य के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए बीसीसी/आईईसी सहित विभिन्न गतिविधियों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करके आयुष पद्धतियों के समग्र विकास और संवर्धन के लिए उनके प्रयासों का समर्थन कर रही है।

शिवराज चौहान ने आय और सुरक्षा गारंटी दी

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तंबाकू जैसी हानिकारक फसल के स्थान पर लाभदायी वैकल्पिक फसलें उपलब्ध कराने से लेकर एमएसपी पर ऐतिहासिक खरीदी, फसल बीमा योजना में क्रांतिकारी सुधार और सख्त निगरानी व्यवस्था के जरिए किसानों की आय और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक सभा में सांसदों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देते हुए बताया कि मोदी सरकार ने केवल किसानों से तंबाकू की उपज छोड़ने की अपील नहीं की, बल्कि जिन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है, वहां हाइब्रिड मक्का, मिर्च, शकरकंद, कपास, आलू, चिया, फीड बीन, लोबिया, रागी, रेड ग्राम, गन्ना, सोयाबीन, ज्वार और मूंगफली जैसी लाभकारी फसलों को मजबूत विकल्प के रूप में चिन्हित किया गया है ताकि किसानों की नकदी आमदनी सुरक्षित रहे।

उन्होंने कहा कि देश में अधिकांश किसानों के पास छोटी जोत है, ऐसे में छोटे किसानों के लिए केवल एक फसल पर निर्भर रहना जोखिम भरा है, इसलिए सरकार ने एकीकृत खेती (इंटीग्रेटेड फार्मिंग) के कई मॉडल तैयार कर विभिन्न राज्यों में उनका डेमो शुरू

किया है। इन मॉडलों के तहत किसान अनाज (गेहूं, धान), सब्जियाँ, फल, पशुपालन, मछली पालन, मधुमख्खी पालन, बकरी पालन और कृषि वानिकी जैसी गतिविधियां एक साथ अपनाकर साल भर स्थिर और बेहतर आमदनी अर्जित कर सकते हैं।

श्री चौहान ने कहा कि किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं, धान, दलहन और तिलहन सहित सभी प्रमुख फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है और वर्तमान सीजन में एमएसपी पर फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह मोदी सरकार ही है जिसने तुअर, मसूर और उड़द जैसी दलहन फसलों के लिए यह व्यवस्था की है कि किसान पंजीयन कराकर जितना भी बेचने के लिए लाएंगे, सरकार पूरी खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे दाल उत्पादक किसानों को बड़ा सहारा मिला है।केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कई-कई महीनों तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता था, लेकिन मोदी सरकार ने नियमों में व्यापक संशोधन कर यह प्रावधान कर दिया है कि एक अकेले किसान की फसल को भी नुकसान होगा तो बीमा कंपनी को उसका मुआवजा देना ही पड़ेगा। उन्होंने बताया कि अब उपज के आंकड़े आने के बाद ख्क दिनों के भीतर यदि बीमा दावा राशि किसान के खाते में नहीं पहुंचती, तो बीमा कंपनियों और राज्यों - दोनों को क्ख प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करना होगा ताकि किसी भी किसान को देरी की दोहरी मार न झेलनी पड़े। श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' के संकल्प के अनुरूप फसल बीमा और अन्य योजनाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि कृषि रक्षक पोर्टल सहित विभिन्न डिजिटल माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच की जा रही है और जहां भी गड़बड़ी पाई जाती है, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है; साथ ही विभिन्न राज्यों, विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों में हाल के वर्षों में किसानों के खातों में डीबीटी के जरिए फसल बीमा की हज़ारों करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा कराई गई है जो किसान हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں عظیم الشان محفل حسن قرأت کا انعقاد

نورانی محفل میں دہلی و بیرون دہلی کے علاوہ ایران و مصر کے قراء کرام نے اپنے فن قرأت کا مظاہرہ کیا

نئی دہلی (ٹاپ بیورو) انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر لودھی روڈ نئی دہلی کے زیر اہتمام ایک عالمی محفل حسنِ قرأت کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک و بیرون ملک سے تشریف لائے قراء کرام نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔اس محفل میں مصر، ایران اور ملک کے مختلف شہروں کے ممتاز قراء کرام نے اپنی خوش الحانی اوردلنشین تلاوتوں سے سامعین کے دلوں کو منور کردیا۔اس پُر برکت محفل حسن قرأت کی نظامت کے فرائض کل ہند مسابقاتِ قرآنی کے کنوینر قاری یاسین نے بحسن وخوبی انجام دیئے۔اس موقع پر انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے آل پروگرام کنوینر جناب قمر احمد صاحب نے تمام مہمانان گرامی کا استقبال کیا ساتھ ہی تسمیہ آل انڈیا ایجوکیشنل اینڈ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کے صدر ڈاکٹر سید فاروق صاحب نے تمام قراء کرام کی گلپوشی کی اور اُن کو تحفہ وتحائف سے نوازا۔آخر میں اسلامک سینٹر کے صدر جناب سلمان خورشید صاحب کلمات تشکر پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی نورانی اور پُر برکت محافل کا انعقاد انڈیا اسلامک سینٹر پہلے بھی کرتا رہا ہے اور انشاء اللہ بھی آئندہ بھی جاری رہے گا۔ان قرآنی محافل کے انعقاد سے نوجوانوں میں قرآن کریم کو پڑھنے اور پڑھانے کا جذبہ پیدا ہوگا اور معاشرے میں دینی شعور بیدار ہوگا۔قرآن پاک کا پڑھنا، سننا اور سنانا ثواب میں شامل ہے۔اللہ تعالیٰ کے کلام کو جتنا پڑھا جائے اتنا ثواب ہے اسے سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔اس موقع پر حیدرآباد سے تشریف ڈاکٹر سید مرتضیٰ نقشبندی نے مصری قراء کرام کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔اس محفل قرآنی کا آغاز مظفرنگر سے تشریف لائے قاری محمد زبیر قاسمی کی تلاوت سے آغاز ہوا۔اس کے بعد قاری جنید قاسمی اور قاری عبدالباسط قاسمی نے تلاوت پیش کی۔اس بابرکت محفل میں ایران سے تشریف لائے بین الاقوامی قاری ابوالفضل قدرتی اپنی بہترین تلاوت سے اس روحانی محفل کو پُرنور بنادیا ان کی دلکش اور مسحور کن آواز سے سامعین محظوظ کیا۔پروگرام کے درمیان نماز عصر کا وقفہ ہوا، نماز عصر کے بعد مصری قراء کرام نے تلاوت پیش کی۔حاضرین نے اس روحانی اجتماع کو بے حد سراہا اور آءندہ بھی اس طرح کے پروگرام منعقد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔اس روحانی محفل میں کثیر تعداد میں اہم شخصیات نے شرکت کی جس میں انڈیا اسلامک سینٹر کے سابق صدر جناب سراج قریشی، ڈاکٹر پرویز میاں سابق چیرمین دہلی حج کمیٹی، قاری عبدالصمد قاسمی، ڈاکٹر افروز الحق، مولانا حسیب صدیقی صدر ملی کونسل یوپی، سلمان چشتی جے پور، ڈاکٹر محمد مرتضیٰ حیدرآباد کے علاوہ کثیر تعداد میں علماء کرام ودیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔آخر میں مصری قاری عبداللہ فلیحی نے دعا کی اور اسی کے ساتھ یہ محفل حسن قراءت افطار کے وقت اختتام کو پہنچی۔

مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی: نئی دہلی کے ایوانِ غالب میں عالمی یومِ قدس کانفرنس کا انعقاد

نئی دہلی: مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی اوران کے جائز حقوق کی حمایت کے لیے آج نئی دہلی کے ایوانِ غالب میں شیعہ کونسل آف انڈیا کے زیر اہتمام بین الاقوامی یوم قدس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔اس اہم پروگرام میں مختلف ملی، سماجی اور سیاسی شخصیات، دانشوروں، علمائے کرام اور انسانی حقوق کے کارکنان نے شرکت کی اور فلسطینی عوام کی جدوجہد آزادی کے ساتھ اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔مقررین نے اس موقع پر کہا کہ یوم قدس ماہِ رمضان کے آخری جمعہ کا دن ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں اور انصاف پسند انسانوں کے لیے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اوران کے حقِ خودارادیت کے دفاع کا دن ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ دن خصوصاً غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہارِ یکجہتی، اور صہیونی مظالم کے نتیجے میں شہید ہونے والے تقریباً 75 ہزار فلسطینی شہداء کے غمزدہ خاندانوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو تسلی دینے اور ان کے درد کو محسوس کرنے کا دن ہے۔کانفرنس کے دوران مقررین نے فلسطین کی موجودہ صورت حال، اسرائیلی جارحیت اور فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم پر تفصیلی روشنی ڈالی۔انہوں نے کہا کہ فلسطینی عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی سرزمین، آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کے حصول کے لیے ظلم، جبر اور ناجائز قبضے کے خلاف مسلسل جدوجہد کررہے ہیں۔اس جدوجہد میں دنیا کے انصاف پسند لوگوں کی اخلاقی اور انسانی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینی عوام کی آوازبنیں اوران کی حمایت کریں۔مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ یوم قدس محض ایک علامتی دن نہیں بلکہ ایک عالمی پیغام ہے جو مسلمانوں اور انسانیت دوست قوتوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ بیت المقدس اور فلسطین کا مسئلہ پوری انسانیت کے ضمیر کا امتحان ہے۔انہوں نے کہا کہ جب تک فلسطینی عوام کو ان کی جائز آزادی اور حقوق نہیں مل جاتے، عالمی ضمیر کو بیدار کرنے کی کوششیں جاری رہنی چاہئیں۔اجلاس میں شریک مقررین اور شرکاء نے فلسطینی علاقوں میں جاری اسرائیلی جارحیت اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف ہونے والے مظالم کو روکنے اور خطے میں پائیدار امن قائم کرنے کے لیے مؤثر اور عملی اقدامات کریں۔کانفرنس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ مسئلۂ فلسطین کا واحد منصفانہ اور پائیدار حل یہی ہے کہ فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین، آزادی اور خودمختاری کا مکمل حق دیا جائے۔مقررین نے کہا کہ دنیا بھر میں منعقد ہونے والے ایسے پروگرام عالمی رائے عامہ کو بیدار کرنے اور فلسطینیوں کے حقِ خودارادیت کی حمایت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر قاتلانہ حملہ جمہوری اقدار پر سنگین حملہ: انڈین مسلمس فار سول رائٹس۔سرکار اور جموں وکشمیر پولیس کی کارکردگی پر اٹھائے سنگین سوالات

نئی دہلی (ٹاپ بیورو): انڈین مسلمس فار سول رائٹس (IMCR) نے جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ پر حالیہ دنوں میں ہونے والے قاتلانہ حملے کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے نہ صرف ایک اہم قومی سیاسی شخصیت بلکہ ملک کی جمہوری اقدار، آئینی نظام اور سیاسی رواداری پر ایک سنگین حملہ قرار دیا ہے۔اس سلسلے میں انڈین مسلمس فار سول رائٹس کی مجلس عاملہ کا ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں تنظیم کے ذمہ داران اور اراکین نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اس نوعیت کے واقعات نہ صرف ملک کے سیکورٹی نظام کی کمزوری کو بے نقاب کرتے ہیں بلکہ جمہوری فضا کو بھی شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔اجلاس کے بعد میڈیا کو جاری کیے گئے ایک باضابطہ بیان میں انڈین مسلمس فار سول رائٹس کے چیئرمین اور سابق رکن پارلیمنٹ محمد ادیب نے مرکزی حکومت اور جموں وکشمیر پولیس کی کارکردگی پر سنگین سوالات اٹھاتے ہوئے سخت تنقید کی۔انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک سینئر قومی رہنما اور ملک کی اہم سیاسی شخصیت ہیں جنہیں زیڈ سیکورٹی فراہم کی گئی ہے۔اس کے باوجود ان پر قاتلانہ حملہ ہونا نہ صرف سیکورٹی نظام کی سنگین ناکامی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ یہ پورے انتظامی ڈھانچے پر ایک بڑا سوالیہ نشان بھی کھڑا کرتا ہے۔محمد ادیب نے کہا کہ اگر ایک زیڈ سیکورٹی حاصل کرنے والا لیڈر بھی محفوظ نہیں ہے تو پھر عام شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے بارے میں کیا یقین کیا جا سکتا ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیکورٹی کے دعووں اور زمینی حقیقت کے درمیان واضح تضاد موجود ہے، جس کی وجہ سے عوام کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ ریاست میں قانون ونظم کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے اور سیکورٹی ادارے اپنی بنیادی ذمہ داریوں کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں۔اس طرح کے خطرناک واقعات نہ صرف عوام میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں بلکہ جمہوری ماحول کو بھی مجروح کرتے ہیں۔میٹنگ میں شریک پٹنہ ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس جسٹس اقبال احمد انصاری نے بھی اس واقعہ پر شدید حیرت اور افسوس کا اظہار کیا۔انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور حیران کن بات ہے کہ ایک اہم قومی سیاسی لیڈر پر عوامی تقریب کے دوران قاتلانہ حملہ ہو جاتا ہے اور اس کے باوجود سرکار اور پولیس خاموش تماشائی بنی نظر آتی ہے۔انہوں نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جانچ کے نام پر محض لیپا پوتی کی جا رہی ہے، جو نہ صرف افسوسناک ہے بلکہ اس سے پولیس اور انتظامیہ پر عوام کا اعتماد بھی کمزور ہوتا ہے۔آئی۔ایم۔سی۔آر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ کی اعلیٰ سطحی، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور اس حملے کے ذمہ دار عناصر کو فوری طور پر قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔تنظیم نے واضح کیا کہ اس معاملے میں کسی بھی قسم کی لاپروائی یا پردہ پوشی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور عوام کو اس واقعہ کی مکمل حقیقت جاننے کا پورا حق حاصل ہے۔انڈین مسلمس فار سول رائٹس نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ تنظیم کے چیف پیٹرن بھی ہیں، اس لیے یہ واقعہ تنظیم کے لیے خصوصی طور پر باعث تشویش ہے۔تنظیم نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ سمیت تمام اہم سیاسی اور سماجی شخصیات کی سیکورٹی کا ازسرنو جائزہ لیا جائے اور سیکورٹی کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے خطرناک واقعات کو روکا جا سکے۔تنظیم نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ ملک میں جمہوری اقدار، قانون کی حکمرانی اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کرتی رہے گی اور کسی بھی ناانصافی، ناا ہلی یا سیکورٹی کی ناکامی پر خاموش نہیں رہے گی۔

नैसकॉम वैश्विक सम्मेलन 2026 में शामिल हुए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू

दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू आज नई दिल्ली में आयोजित नैसकॉम वैश्विक सम्मेलन 2026 में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 'राष्ट्र निर्माण में प्रौद्योगिकी की भूमिका' विषय पर भाषण दिया। अपने संबोधन में श्री संधू ने समावेशी और भविष्य के लिए तैयार भारत के निर्माण में नवाचार, डिजिटल अवसंरचना और जिम्मेदार प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया।

विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने 7 विदेशियों को 11 दिन की हिरासत में भेजा

दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने सात विदेशियों को ग्यारह दिन की हिरासत में भेज दिया है। इन सात विदेशियों में, तीन यूक्रेन के नागरिक हैं, जिन्हें दिल्ली से हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा तीन को लखनऊ और एक अमरीकी नागरिक को कोलकाता से पकड़ा गया है। आरोप है कि ये सभी नागरिक वीजा पर भारत आए थे, पहले यह मिजोरम में दाखिल हुए, जो एक संरक्षित क्षेत्र है। उसके बाद ये म्यांमा गए और जातीय युद्ध समूहों से संपर्क किया।

सोनम वांगचुक ने सरकार की संवाद पहल का स्वागत किया

नई दिल्ली। कई महीनों के कानूनी और राजनीतिक संघर्ष के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता और सुधारवादी सोनम वांगचुक ने सरकार की हाल ही में शुरू की गई 'सार्थक और रचनात्मक संवाद' पहल पर संतोष व्यक्त किया है। रिहाई के बाद उन्होंने जोर दिया कि उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत कानूनी जीत नहीं है, बल्कि लद्दाख, उसके लोगों और देश के लिए व्यापक 'विन-विन-विन' परिणाम हासिल करना है। वांगचुक ने कहा कि उनके कानूनी दल को उम्मीद थी कि वे सकारात्मक निर्णय प्राप्त करेंगे, लेकिन उनका लक्ष्य व्यक्तिगत राहत से आगे बढ़कर पर्यावरण संरक्षण, क्षेत्रीय स्वायत्तता और लोकतांत्रिक संवाद को सफल बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ सहयोगात्मक समाधान भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करेगा और जनता का विश्वास बढ़ाएगा।सोनम वांगचुक ने सरकार के कुछ आदेशों को रद्द करने और संवाद के लिए आमंत्रण देने के कदम का स्वागत करते हुए इसे 'भरोसा बहाल करने की दिशा में बड़ा कदम' बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से आंदोलन का यही लक्ष्य रहा है। वांगचुक ने अपने संघर्ष का जिक्र करते हुए बताया, 'हमने संवाद के लिए प्रयास किए—लेह से दिल्ली तक पैदल यात्रा की, प्रदर्शन आयोजित किए और लगातार अपील की।'

चंद्रबाबू नायडू ने एलपीजी और प्राकृतिक गैस आपूर्ति की समीक्षा की

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने आज अमरावती स्थित राज्य सचिवालय में एक बैठक में राज्य में एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में वर्तमान में लगभग 14 हजार मीट्रिक टन एलपीजी का भंडार उपलब्ध है और अतिरिक्त आपूर्ति शीघ्र होने की उम्मीद है। उन्होंने आश्वासन दिया कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है और अधिकारियों को अस्पतालों, छात्रावासों और मंदिरों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। श्री नायडू ने कहा कि राज्य में अगले 15 दिनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त गैस भंडार है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के प्रशासनिक फेरबदल पर जताया असंतोष

कोलकाता। (टॉप ब्यूरो) तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए प्रशासनिक फेरबदल पर असंतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे पत्र में कहा कि विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर चुनाव आयोग ने प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों को हटा दिया। तबादलों में मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक शामिल थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस कदम को राजनीतिक गलियारे में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने भी इस फेरबदल पर ध्यान देने की बात कही है। वहीं, चुनाव आयोग ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासनिक फेरबदल पर मुख्यमंत्री की नाराजगी ने राजनीतिक चर्चा तेज कर दी है। राज्य में आगामी चुनाव में सभी दलों के लिए यह मामला रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे अचानक किए गए प्रशासनिक बदलाव चुनावी प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं और इससे प्रशासनिक समन्वय में अस्थिरता पैदा हो सकती है। विशेष रूप से पुलिस और प्रशासनिक विभागों में शीर्ष अधिकारियों के तबादले चुनावी तैयारियों और चुनाव आयोग के निर्देशों के पालन पर सवाल खड़े कर सकते हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि भविष्य में इस तरह के फैसले चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद न लिए जाएँ, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी निष्पक्षता पर किसी प्रकार का संदेह न रहे। पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रशासनिक फेरबदल को राजनीतिक रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए।

वहीं, विपक्षी दलों ने भी इस मसले को उठाते हुए चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के अचानक बदलावों से राज्य में चुनावी माहौल प्रभावित हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह मुद्दा आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान सभी दलों के लिए चुनावी रणनीति का हिस्सा बन सकता है।

चुनाव आयोग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आने के बावजूद, इस मामले ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। आगामी सप्ताह में चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर बयान आने की संभावना है।

कई राज्यों में तूफान का ऑरेंज अलर्ट

नई दिल्ली। मौसम विभाग ने कल नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाएं चलने के साथ तूफान आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों के दौरान झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी इसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

मौसम विभाग ने बुधवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में छिटपुट स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने जनता से इस दौरान सावधानी बरतने और जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। विभाग ने विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही नदी और नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने कहा कि बिजली और तेज हवाओं से जुड़ी सुरक्षा सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है। राज्य प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभागों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों में आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे आने वाले तूफान और बारिश की नवीनतम जानकारी के लिए लगातार अपडेटेड मौसम बुलेटिन पर ध्यान दें। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसमी बदलाव के चलते आने वाले दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं की स्थिति बनी रह सकती है।

دہلی میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی یاد میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد، مختلف مذاہب اور سیاسی حلقوں کی اہم شخصیات کی شرکت

نئی دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی یاد میں منعقد تعزیتی اجلاس کا منظر، جس میں مختلف مذاہب، سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات اظہارِ خیال، اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا۔ (تصویر: محمد اشرف)

نئی دہلی (ٹاپ بیورو): دارالحکومت نئی دہلی کے کانسٹی ٹیوشن کلب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی یاد میں ایک تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مختلف مذاہب، سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں سے تعلق رکھنے والی ممتاز شخصیات نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یہ پروگرام انڈین مسلمس فار سول رائٹس (IMCR) اور ایسوسی ایشن فار پروٹیکشن آف سول رائٹس (APCR) کی مشترکہ کوششوں سے منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے سفیر ڈاکٹر محمد فتحلی نے آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت پر گہرے رنج وغم کا اظہار کیا اور کہا کہ بھارت کے عوام نے جس طرح ایران کے ساتھ ہمدردی اور حمایت کا اظہار کیا ہے، ایران اس پر ہندوستانی عوام کا تہہ دل سے شکر گزار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں تھا، لیکن ان دونوں ممالک نے دھوکہ دیتے ہوئے ایران پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے میں ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کیا گیا اور ایک اسکول پر بمباری کر کے معصوم بچیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی سفیر نے واضح کیا کہ ایران اپنے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے اور ایرانی افواج نے عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے بجائے صرف امریکہ اور اسرائیل کی تنصیبات کو ہدف بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا موقف واضح ہے کہ وہ کبھی بھی عام شہریوں کو نشانہ نہیں بناتا۔ آئی ایم سی آر کے صدر اور سابق رکن پارلیمنٹ محمد ادیب نے اپنے خطاب میں کہا کہ بھارت مہاتما گاندھی کی سرزمین ہے اور ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے وزیراعظم اسرائیل کے وزیراعظم سے ملاقات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمیشہ امن کا پیامبر رہا ہے اور دہشت پسندانہ سوچ کو کبھی فروغ نہیں دیتا۔ محمد ادیب نے کہا کہ اسرائیل کا وزیراعظم ایک جنگی مجرم ہے اور جب ہمارا وزیراعظم اس سے گلے ملتا ہے تو یہ ہمارے لیے شرم کا باعث بنتا ہے۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے صدر اور سابق وزیر خارجہ سلمان خورشید نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ اور ان کی جماعت آل انڈیا کانگریس کمیٹی ایران پر کی گئی اس جارحانہ کارروائی کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران اور حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور دنیا میں دہشت کو فروغ دینے والی طاقتوں کی حمایت نہیں کرتے۔ سلمان خورشید نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کی جانب سے اظہار یکجہتی کے لیے ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا جا چکا ہے جہاں سپریم لیڈر کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا گیا، جبکہ جلد ہی انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کی جانب سے بھی اس سانحے پر ایران کے سفارت خانے کا دورہ کیا جائے گا۔ دہلی کے سابق لیفٹیننٹ گورنر نجیب جنگ نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران ہمارا پڑوسی اور قدیم دوست ملک ہے جس کے ساتھ بھارت کے تاریخی تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کا حملہ قابل مذمت ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں جس طرح عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے باوجود بھارت سرکار کی خاموشی انتہائی افسوسناک ہے۔ نجیب جنگ نے کہا کہ اگر ہم ایران کے سپریم لیڈر کے قتل کی دولفظوں میں بھی مذمت نہیں کر سکتے تو ہمیں اس پر شرم آنی چاہیے۔ رکن پارلیمنٹ پروفیسر منوج جھا نے بھی مرکزی حکومت اور بی جے پی کی پالیسیوں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر کی جرات کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے سرینڈر کرنے کے بجائے موت کو قبول کرنا پسند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی پوری ہمدردی ایران اور اس کی عوام کے ساتھ ہے۔ جماعت اسلامی ہند کے امیر انجینئر سید سعادت اللہ حسینی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کا وزیراعظم ایک عالمی مجرم ہے جس کے خلاف دنیا کے مختلف ممالک میں گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے اور آج دنیا میں عالمی قانون کی بالادستی کمزور پڑتی نظر آ رہی ہے۔ سابق جج جسٹس اقبال انصاری نے کہا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی نظام شدید بحران کا شکار ہے۔ انہوں نے آیت اللہ علی خامنہ ای کی شہادت کو جرات مندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے ایران کے خلاف اس جارحانہ کارروائی کی سخت مذمت کی۔ اس موقع پر سرو دھرم سنسد کے چیف اور سناتن دھرم کے معروف پیشوا گوسوامی سشیل جی مہاراج نے کہا کہ تمام مذاہب کے لوگ ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ایران ہمارا پرانا دوست ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف مذاہب کے ماننے والے متحد ہو کر اسرائیل اور امریکہ کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہیں۔ اجلاس سے خطاب کرنے والوں میں سابق رکن پارلیمنٹ اور کانگریس لیڈر کنور دانش علی، ممتاز سماجی کارکن فادر جان دیال، دھارمک جن مورچہ کے قومی صدر محمد سلیم انجینئر، سابق سفیر اشوک کمار شرما اور پلاننگ کمیشن کی سابق رکن سیدہ سیدین حمید سمیت متعدد اہم شخصیات شامل تھیں۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض معروف سماجی کارکن ندیم خان نے انجام دیے جبکہ اختتامی کلمات اور اظہار تشکر آئی ایم سی آر کے جنرل سکریٹری مسعود حسین نے پیش کیا۔ اس موقع پر مختلف مذاہب کے دھرم گرو۔ دہلی میں قائم ایران اور عراق سفارت خانے سے کئی ڈپلومیٹ اور دہلی و اطراف کے علاقوں سے تعلق رکھنے والی متعدد اہم سماجی، سیاسی اور علمی شخصیات بھی موجود تھیں جنہوں نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔

سلیم پور کے مدرسہ اشرف العلوم میں روحانی محفلِ تکمیل قرآن، علاقے کی معزز شخصیات کی شرکت

نئی دہلی: مدرسہ اشرف العلوم جے بلاک سلیم پور دلی میں تراویح میں قران کریم کے اختتام پر ایک نورانی وروحانی محفل منعقد کی گئی جس میں مدرسہ کے طلبہ اور اساتذہ سامعین کرام کے علاوہ علاقے کی سرکردہ شخصیات و ائمہ علماء کرام کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس نورانی وروحانی محفل کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے ہوا اس پروگرام کے مہمان خصوصی معروف عالم دین مولانا محمد اسرائیل حسینی وجامعی نے قران کریم ،رمضان المبارک اور حافظ قران کی عظمت وفضیلت پر قران وحدیث کی روشنی میں موثر ومدلل بیان کیا اور کہا کہ اللہ تعالی نے قران مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القران یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قران نازل کیا گیا جس میں تمام انسانوں کے لئے ہدایت ہے انہوں نے کہا کہ قران کریم کی تلاوت اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا مسلمانوں کی زندگی کا اصل مقصد ہونا چاہیئے خاص طور پر رمضان المبارک میں قران سے تعلق کو مضبوط کرنا اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا سبب بنتا ہے مولانا محمد اسرائیل نے حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ قیامت کے دن حافظ قران سے کہا جائے گا قران کریم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات طے کرتے جاؤ جیسے دنیا میں قران پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قران کی تعلیم اور حفظ قران کی طرف راغب کریں خطاب کے اختتام پر مولانا محمد اسرائیل نے حاضرین کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی تلقین کی مدارس مساجد اور علماء کی عزت اور ان کی مدد کرنے کی طرف توجہ دلائی اس پروگرام کے اخیر میں مولانا نے ملک کو ملت اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی اور مسلمانوں و انسانوں کی کامیابی کے لئے رقت آمیز دعا کرائی اس پروگرام میں بطور خاص انجینئر محمد کفایتاللہ مفتی اشرف اور اظہر بھائی حافظ ذیشان مولانا محفوظ ندوی نے شرکت کی قران کریم سنانے والے اور سننے والے کو سامعین کی جانب سے تحائف اور انعام سے نوازا گیا پروگرام کے بعد مفتی فیاض احمد قاسمی مہتمم مدرسہ ہذا نے تمام حاضرین کی ضیافت کا اہتمام کیا۔

مغربی بنگال کے گورنر بنے آر این روی، کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے دلایا حلف

کلکتہ: تمل ناڈو کے سابق گورنر آر این روی اب مغربی بنگال کے گورنر بن گئے ہیں۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سجوئے پال نے انہیں گورنر کے عہدے کا حلف دلایا۔ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اور اسمبلی اسپیکر بمان بنرجی بھی موجود رہے۔ آر این روی کی تقرری سی وی آنند بوس کے اچانک استعفیٰ کے بعد ہوئی، جنہوں نے گزشتہ 5 مارچ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ آر این روی کو ایسے وقت پر بنگال کا گورنر بنایا گیا ہے، جب بنگال کی سیاست میں سیاسی ہلچل جاری ہے۔ آئندہ چند دنوں میں الیکشن کمیشن ریاست میں انتخاب کی تاریخوں کا اعلان کرنے والا ہے۔ آر این روی نے سابق گورنر سی وی آنند بوس کی جگہ لی ہے، جنہوں نے حال ہی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے حال ہی میں کئی گورنروں کا رد وبدل کیا ہے، جس کے تحت آر این روی کو تمل ناڈو سے مغربی بنگال بھیجا گیا ہے۔ واضح رہے کہ آر این روی کا انتظامی اور سیکورٹی معاملات کا وسیع تجربہ ہے۔ وہ 1976 بیچ کے انڈین پولیس سروس (آئی پی ایس) افسر رہے ہیں اور کئی اہم انٹیلی جنس اور سیکورٹی ایجنسیوں میں ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ انہوں نے قومی سلامتی کے امور میں بھی اہم کردار ادا کیا اور کچھ عرصے کے لیے ہندوستان کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی رہے۔ بنگال کے گورنر بننے سے قبل آر این روی ناگالینڈ اور میگھالیہ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شمال مشرقی ہندوستان میں ناگا امن مذاکرات میں مرکزی حکومت کے نمائندے کے طور پر اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کے انتظامی تجربے کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک سخت اور فیصلہ کن افسر مانا جاتا ہے۔ تاہم ان کی تقرری کے حوالے سے ریاست کی سیاست میں ردعمل بھی سامنے آئے ہیں۔